विमुद्रीकरण का बजट पर प्रभाव

Dr. Ramesh Kumar
Associate Prof. of Commerce
Government PG College, Hisar

सारांश : कानूनी रूप से किसी मुद्रा इकाई के मूल्य को अमूल्य कर देना ही विमुद्रीकरण है। जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, नोटों की जमाखोरी तथा आतंकवाद में नकली करेन्सी का प्रयोग होने लगता है तो मुद्रा की पुरानी इकाई को नई इकाई के साथ प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिग व्यवस्था के पास निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है। 8 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा का बजट पर स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला । किसानों के लिए अगले पांच वर्षों में आय दोगुनी करने के लिए बजट में कृषि कर्ज प्रदान करने के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। महिला और बाल विकास के लिए एक लाख 84 हजार करोड़ रूपये दिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 3 लाख 96 हजार करोड़ रूपये आवंटित हुए है विशेष रूप से हाइवे के लिए 64,900 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 1,30,215 करोड़ रूपये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गये है। बजट 2017–2018 एक ओर कृषि, सामाजिक क्षेत्र, अवसरचंना, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और रोजगार सृजन में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की सरकार की दृढ प्रतिबद्धता और दूसरी ओर साथ ही साथ राजकोषीय और राजस्व घाटे को सीमित रखते हुए लक्ष्य के अनुरूप, आवंटित फंडस में वृद्धि की गई है जो बजट की बेहतरीन उपलब्धि साबित हुई है। राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, रीयल एस्टेट सस्ते होंगे, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी, अर्थव्यवस्था लेस कैश की ओर बढ़ेगी, आतंकवाद, हवाला कारोबार, शेडो बैंकिग, ब्याज दर तथा ईएमआई का बोझ कम होगा। 100 प्रतिशत करेंसी के चलन में आने से बैंक शक्तिशाली बनेंगें। आयकर छूट से कमजोर पड़ी हुई उपभोक्ता की मांग बढेगी तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 2017–2018 का बजट लोक लुभावन मुद्दों से दूरी बनाते हुए समाज के ईमानदार व कर्मशील व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास है।

संकेतशब्द : विमुद्रीकरण, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, मुद्रा, बजट, निवेश

....

भूमिका : कानूनी रूप से किसी मुद्रा इकाई (जैसे 500 और एक हजार रूपये) के मूल्य को अमान्य कर देना ही है। मोटे तौर पर यह राष्ट्रीय मुद्रा में एक प्रकार का परिवर्तन है। जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और लोग नोटों की बैंको से दूर जमाखोरी करने लगते हैं तथा आतकंवाद में फेक करेंसी का प्रयोग होने लगता है तो मुद्रा की पुरानी ईकाई को एक नई मुद्रा इकाई के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है जो पुनः बैकिंग प्रकिया में शामिल हो जाती है और बैंकिंग सिस्टम के पास निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की तो सारे भारत में जैसे भुकम्प सा आ गया। यह घोषणा कुछ लोगों को युद्ध के ऐलान से भी घातक लगी व उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशों-हवाश खो बैठे व हड़बड़ाहट में ज्वैलर्स के पास दौड़े व उल्टे सीधे दामों में सोना खरीदने लगे। अगले दिन से ही एटीएम व बैंक लोगों के स्थाई पत्ते बन गए। लंबी–लंबी लाइने भारत की बढती जनसंख्या को दिखाने लगी। विपक्षी दल पूरी एकजुटता से सरकार के निर्णय को असफल व देश के लिए घातक सिद्ध करने में लगे रहे जबकि सरकार इसे देश की विकास दर को बढाने वाला निर्णय कहती हुई नजर आई।

वर्ल्ड बैंक के आकड़ों के मुताबिक दक्षिण एशिया में वर्ष 2015 में भारत की विकास दर सबसे अधिक रही। 2015 में भारत में 7.57 प्रतिशत, पाकिस्तान में 5.54 प्रतिशत, श्री लंका में 4.79 प्रतिशत, नेपाल में 3.36 प्रतिशत, भूटान में 3.25 प्रतिशत, अफगानिस्तान में 1.52 प्रतिशत मालद्वीव में 1.51 प्रतिशत सक्ल घरेलू उत्पाद रहा। नोटबंदी के उपरांत अर्थ व्यवस्था की कमियों को दूर करके विकास की रफतार को तेजी प्रदान करने से अर्थव्यवस्था मे नयी जान आएगी व इसका नोटबंदी पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। राजनीति और चुनाव प्रकिया पारदर्शी बनेगी, रीयल एस्टेट सस्ते होगें, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी, अर्थव्यवस्था लेसकैश की ओर बढेगी, आतंकवाद, हवाला कारोबार, शेडों बैकिंग, ब्याज दर तथा ईएमआई का बोझ कम होगा । 100 प्रतिशत करेंसी के चलन में आने से बैंक शक्तिशाली बनेंगे तथा इफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बजट 2017–18 एक और कृषि, सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना और रोजगार सृजन में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढाने की सरकार की दृढ प्रतिबद्धता और दूसरी ओर साथ ही साथ राजकोषीय घाटे के 3.2 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप रहते हुए आवंटित फंडस में वृद्धि की गई है।

विमुद्रीकरण का बजट पर प्रभाव : बजट का विस्तार से विश्लेषण करने के उपरांत नोटबंदी के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। कर दायरे में 5 प्रतिशत का नया सलैब लाकर 10 प्रतिशत का सलैब खत्म कर दिया गया है। यानि अब 5 प्रतिशत की सलैब के बाद सीधा 20 प्रतिशत का सलैब होगा। इस प्रकार से पैन कार्ड धारक को अधिकतम 12,875 करोड़ रूपये सालाना की एक बड़ी छूट बजट में प्रदान की गई

हैं। उसके साथ ही कर दायरे से बाहर रहने वाले व्यक्तियों से भी राष्ट्र निर्माण के लिए 5 प्रतिशत टैक्स देने की अपील की गई है जिसका फायदा निश्चित रूप से टैक्स बढोतरी के रूप में राष्ट्र को मिलेगा।

किसानों के लिए अगले पांच वर्षों में आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बजट में कृषि कर्ज प्रदान करने के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसमें छोटे किसानों के सिंचाई प्रोजेक्टस के लिए 5000 करोड़ रूपये का अलग फंड बनाया गया है। इस बजट में सभी गावों में 15 महीनों में बिजली पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है।

इसी तरह से युवाओं को लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने के प्रस्ताव दिया गया है व 100 इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोले जाएगें। इससे युवाओं की ट्रेनिंग के लिए अन्य संस्थाओं का बोझ कम होगा। स्कूलों में शिक्षा के स्तर को निरतंर उठाने व शिक्षा की गुणवता बढाने के लिए पैमाना तैयार किया जाएगा। इसमें 1,30,215 करोड़ रूपये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गये है।

इफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 3 लाख 96 हजार करोड़ रूपये आवंटित हुए है विशेष रूप से हाइवे के लिए 64,900 करोड़ रूपये का प्रावधान है। महिला और बाल विकास के लिए एक लाख 84 हजार करोड़ रूपये सरकार ने दिए है। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 7353 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं। अब राजनैतिक दल 2000 रूपये से ज्यादा कैश डोनेशन नहीं ले सकगें।

बजट में कैशलेस इकोनॉमी को बढाने के लिए करीब आधा दर्जन प्रावधान किए गयें हैं। इसमें भीम एप्प पर कैशबैक, 10 लाख स्वाइप मशीनें और आधार इनेवल्ड पेमेंट को बढावा देना मुख्य है। इस तरह की एप्पस भी है जिनसे हम कैशलेस नही तो लेसकैश इॅकोनामी के सपने को साकार कर सकते है। इसमें नेट बैंकिग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई–वालेट, भीम एप्प व यूएसएसडी भी कुछ इसी तरह से कार्य करती है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ रूपये आवंटित हुए है इसमें मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रूपये दिए गये हैं। 2019 तक बेघरों और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए एक करोड़ घर बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रूपये का फंड बनाया गया है। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा । इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में 8000 करोड़ रूपये का डेयरी प्रोसेसिंग फंड गठित किया जाएगा। यह सब विमुद्रीकरण के सफल निर्णय के उपरांत ही सम्भव हो पाया है।

किसानों को 10 लाख करोड़ रूपये के ऋण के प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों को 1,87,000 हजार करोड़ रूपये आवंटित करना, 23 हजार करोड़ रूपये से गरीब बेघरों के लिए एक करोड़ मकान बनाना, टूरिज्म,

इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट सेक्टर में सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग, टेक्सटाईल तथा श्रम प्रधान सेक्टर को स्पेशल पैकेज देने, रक्षा बजट व मनरेगा के लिए आवंटित राशि में बढोतरी डेयेरी प्रोसेसिंग फंड का गठन, कमजोर निवेश के महौल में सकारात्मक बदलाव के लिए पब्लिक केपिटल एक्सपेंडिचर में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि, 100 इंटरनेशनल सेंटर खोलने के निर्णय से अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को अप्रत्याशित रूप से बढावा मिलेगा। इस प्रकार से बजट लोक लुभावन मुद्दों से दूरी बनाते हुए समाज के ईमानदार व कर्मशील व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास है।

राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 3.2 फीसदी तक पहुंचाते हुए राजस्व घाटे को 1.8 फीसदी तक सीमीत रखना इस बजट की बेहतरीन उपलब्धि है। इनसे निवेष व रोजगार को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। 12,875 रूपये की आयकर छूट से कमजोर पड़ी हुई उपभोक्ता की मांग बढेगी, परिणामस्परूप उत्पादन तथा रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय को 6482 करोड़ रूपये मिले है। यह पिछले बजट से 87.07 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। इससे भी रोजगार के अवसर बढेंगें 1,30,215 करोड़ रूपये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गये हैं। उत्पादकता बढाने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किये जाएंगे। सभी श्रम कानूनों को मिलाकर उनकी चार श्रेणिया बनाई गयी है– इंडस्ट्रियल रिलेशन, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और काम की परिस्थितियां। राज्यों को विचार करने के लिए मॉडल शाप्स बिल भेजे गए हैं। इनके अमल में आने से महिलाओं के लिए रोजगार बढेंगें तथा श्रमिकों के वेतन से जुड़े कानून में संशोधन हो सकेंगें। एसईजेड में प्लांट लगाने वालों को पूंजीगत निवेश पर 20 प्रतिशत और नॉन–एसईजेड इलाके में 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष सब्सिडी आवंटन की राशि बढाई गई है। पिछले साल की तुलना में 8.6 प्रतिशत ज्यादा इंसेंटिव से कंपनियों को अब 83,492 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा। वर्ष 2015–16 से करों में राज्यों के हिस्से के अंतरण में भारी उछाल देखा गया है। इस प्रवृति को जारी रखते हुए राज्यों को जाने वाले कुल ससांधन, जिसमें करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, अनुदान, ऋण और केन्द्रित प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी निधियां शामिल है तथा इनके लिए राशि में भी वृद्धि की गई है क्योंकि सिद्धांत यह है कि जब राज्य विकास करते है, तब राष्ट्र विकास करता है।

रक्षा के लिए 2 लाख 74 हजार करोड़ रूपये का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए घोषित किया गया है। पिछले वर्ष में यह बजट 2 लाख 49 हजार करोड़ रूपये था। अगले वित्तीय वर्ष मे देश में 5

स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगें । इनका गठन राज्यों की साझेदारी में स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में किया जाएगा।

निष्कर्ष (Abstract) : जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, नोटों की जमाखोरी तथा आतंकवाद में नकली करेन्सी का प्रयोग होने लगता है तो मुद्रा की पुरानी इकाई को नई इकाई के साथ प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिग व्यवस्था के पास निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है। 8 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा का बजट पर स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला । किसानों के लिए अगले पांच वर्षों में आय दोगुनी करने के लिए बजट में कृषि कर्ज प्रदान करने के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। महिला और बाल विकास के लिए एक लाख 84 हजार करोड़ रूपये दिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 3 लाख 96 हजार करोड़ रूपये आवंटित हुए है विशेष रूप से हाइवे के लिए 64,900 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 1,30,215 करोड़ रूपये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गये है। बजट 2017–2018 एक ओर कृषि, सामाजिक क्षेत्र, अवसरचंना, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और रोजगार सृजन में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की सरकार की दृढ प्रतिबद्धता और दूसरी ओर साथ ही साथ राजकोषीय और राजस्व घाटे को सीमित रखते हुए लक्ष्य के अनुरूप, आवंटित फंडस में वृद्धि की गई है जो बजट की बेहतरीन उपलब्धि साबित हुई है। राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, रीयल एस्टेट सस्ते होंगे, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी, अर्थव्यवस्था लेस कैश की ओर बढ़ेगी, आतंकवाद, हवाला कारोबार, शेडो बैंकिग, ब्याज दर तथा ईएमआई का बोझ कम होगा। 100 प्रतिशत करेंसी के चलन में आने से बैंक शक्तिशाली बनेंगें। आयकर छूट से कमजोर पड़ी हुई उपभोक्ता की मांग बढेगी तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 2017–2018 का बजट लोक लुभावन मुद्दों से दूरी बनाते हुए समाज के ईमानदार व कर्मशील व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास है।

सन्दर्भ :

बजट - वित मंत्रालय, भारत सरकार, 2017-2018

आर्थिक सर्वे जनवरी 2017

इकानामिक टाईम्स.काम

बिजनस टाईमस.काम